

हाथरस कांड का प्रभाव: बड़े आयोजनों में

भीड़ प्रबंधन और पुलिस की तैनाती की एसओपी जारी

अमर भास्कर, ब्यूरो

लखनऊ। हाथरस कांड के बाद बड़े आयोजनों में भीड़ प्रबंधन और पुलिस बल की तैनाती के लिए डीजीपी प्रशांत कुमार ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। इसके मुताबिक अब कार्यक्रम में खतरे का आकलन करने के बाद ही आयोजन की अनुमति दी जाएगी। वरिष्ठ अधिकारियों को खुद कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करना होगा। श्रेणीबद्ध सुरक्षा प्राप्त तथा विशिष्ट अतिथियों के आवागमन का मार्ग आम जनमानस के मार्ग से अलग रखा जाएगा। राजपत्रित अधिकारी व स्थानीय मजिस्ट्रेट को प्रभारी नियुक्त किया जाएगा।



दरअसल, क्रिकेट मैच देखने, मॉल, रेलवे स्टेशन, राजनीतिक पार्टियों तथा आध्यात्मिक कार्यक्रमों में भारी भीड़ उमड़ती है। भारी भीड़ होने से भीड़ जनित आपदा अथवा भगदड़ की भी आशंका रहती है। पूर्व में लखनऊ, प्रतापगढ़, वाराणसी, प्रयागराज रेलवे स्टेशन तथा हाथरस में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। इसके दृष्टिगत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिाकरण ने भीड़ प्रबंधन के बारे में कई सुझाव दिए हैं। एसओपी के मुताबिक भीड़ जनित आपदा के दृष्टिगत

कमिश्नरेंट, जिला, रेंज, जोन स्तर पर एक एकीकृत प्रणाली (इंटीग्रेटेड सिस्टम) विकसित की जाएगी। डीएम, सीएमओ, सिविल डिफेंस, अग्निशमन, विभिन्न स्वयंसेवी संगठन तथा स्थानीय पुलिस द्वारा इसे लगातार अपडेट किया जाता रहेगा। आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी विभाग नियमित पूर्वाभ्यास करेंगे। पुलिस लाइन में विशेष आयोजनों में सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण तथा यातायात के दृष्टिगत आवश्यक संसाधनों व उपकरण व प्रशिक्षण का इंतजाम करना होगा। सभी राजकीय व निजी अस्पतालों को भी चिह्नित करना होगा।

सीएम केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के. कविता को राहत नहीं

दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में राज एवेंच्यूर कोर्ट ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। अब आठ अगस्त को सुनवाई होगी। तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केजरीवाल की पेशी हुई। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल से ही गिरफ्तार किया था। मनीष सिसोदिया और के. कविता की भी बड़ी न्यायिक हिरासत

राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदला

राष्ट्रपति कार्यालय और निवास राष्ट्र के प्रतीक

नई दिल्ली। राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर गुरुवार को गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप किया गया। ये हॉल विभिन्न औद्योगिक समारोहों के आयोजन स्थल हैं। राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से जारी एक बयान में जानकारी दी गई।



राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति कार्यालय और निवास राष्ट्र के प्रतीक हैं और जनता की एक अमूल्य विरासत हैं। बयान में कहा गया, इन्हें जनता के लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के माहौल को भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और लोकाचार के अनुरूप बनाने के निरंतर प्रयास किए गए। इसी क्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दो प्रतिष्ठित हॉल दरबार हॉल का नाम

बदलकर गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप किया है। बयान में आगे कहा गया, दरबार हॉल राष्ट्रीय पुरस्कारों की प्रस्तुति जैसे महत्वपूर्ण समारोहों का स्थल है। दरबार शब्द का तात्पर्य भारतीय शासकों और अंग्रेजों की अदालतों और सभाओं से है। भारत के गणतंत्र बनने के बाद इसकी प्रासंगिकता खत्म हो गई है। गणतंत्र मंडप की अवधारणा प्राचीन काल से भारतीय समाज में गहराई से निहित है, जिस वजह से आयोजन स्थल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप किया गया है। इसमें आगे कहा गया, अशोक शब्द का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से है, जो सभी प्रकार दुखों से मुक्त है। इसके अलावा अशोक का तात्पर्य एकता और शांति-पूर्ण सह-अस्तित्व के प्रतीक सम्राट अशोक से है। बयान में आगे कहा गया, सारनाथ अशोक की राजधानी थी। यह शब्द अशोक वृक्ष को भी संदर्भित करता है।

एक नजर

मुख्तार अंसारी के बेटे की याचिका पर अदालत ने यूपी सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को विधायक अब्बास अंसारी की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा। अंसारी ने एक मामले में शीर्ष अदालत से जमानत की मांगी थी। उन पर अपनी पत्नी के मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए कई लोगों को धमकी देकर पैसे वसूलने के आरोप लगा है। पत्नी चित्रकूट जिला जेल में उनसे मिलने आती थी, जहां वह बंद हैं। इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एक मई को अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष जोशी ने पद से इस्तीफे की पेशकश की, दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मिले

नई दिल्ली। बीजेपी के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश की है। यह पेशकश उन्होंने दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान की। सूत्रों के अनुसार, शाह ने जोशी से प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा की और उपचुनाव तक पद पर बने रहने की बात कही।

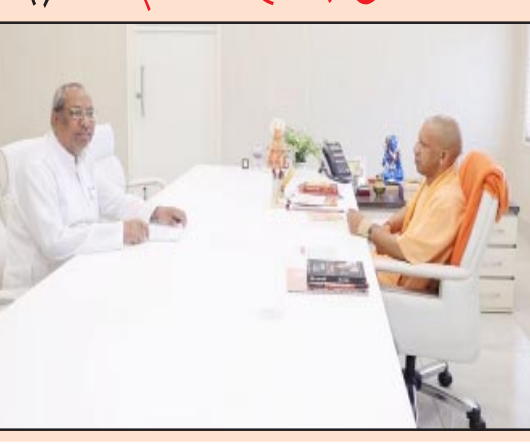


भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी दोनों ही ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। इसे देखते हुए पार्टी में विभिन्न स्तरों पर चर्चा हो रही है कि दोनों प्रमुख पदों पर एक ही समुदाय का

स्वीकार नहीं किया। पार्टी सूत्रों का मानना है कि जोशी की पेशकश के पीछे विभिन्न राजनीतिक और सामुदायिक समीकरण हैं, जिन पर विचार किया जा रहा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आगामी उपचुनाव के मद्देनजर पार्टी नेतृत्व जोशी के इस्तीफे को स्वीकार करता है या उन्हें पद पर बने रहने के लिए मनाता है। इस घटनाक्रम ने राजस्थान की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है।

मुख्यमंत्री योगी से मिले मंत्री संजय निषाद, बताई जा रही शिष्टाचार भेंट

लखनऊ। यूपी सरकार में मंत्री डॉ. संजय निषाद ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि मुलाकात उपचुनाव की तैयारियों को लेकर हुई है। प्रदेश में 1० विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा की जीत के लिए जिन मंत्रियों को प्रभार दिया गया है। उनमें डॉ. संजय निषाद भी हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद जिन लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाए थे। उनमें से एक डॉ. संजय निषाद भी थे। उन्होंने कहा था कि बुलडोजर चलवाने की वजह से जनता ने वोट नहीं दिया। उपचुनाव में जीत के लिए सरकार ने हर सीट पर तीन-चार मंत्रियों एक-एक की टीम बनाकर उतारी है। इस प्रकार कुल 3० मंत्रियों के कंधों पर उपचुनाव जीतने की जिम्मेदारी है।



अगस्त में होगी यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा

बोर्ड ने तारीख व समय सारणी जारी की

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के 6०244 पदों पर सीधी भर्ती-2०23 की लिखित परीक्षा दिनांक 23, 24, 25, 3० और 31 अगस्त 2०24 को आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है। परीक्षा का आयोजन प्रतिदिन दो पालियों में होगा और प्रति पाली में लगभग पांच लाख अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे।



बता दें कि पेपर लीक के कारण पहले हो चुकी यह परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि यह परीक्षा छह माह के अन्दर शुचिता एवं पाददर्शिता के उच्चतम मानकों को दृष्टिगत रखते हुये पुनः आयोजित करायी जाएगी।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस परीक्षा को एक निश्चित समय सीमा के अन्तर्गत पाददर्शी तरीके से उच्चतम मानकों के अनुसार आयोजित करने की प्रतिबद्धता के क्रम में यह कार्यक्रम घोषित किया

गया है। चयन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं शुचितापूर्ण ढंग से कराये जाने के सम्बन्ध में परीक्षा सम्बन्धित विभिन्न व्यवस्थाओं जैसे-परीक्षा की तैयारियों, परीक्षा केंद्रों के चयन, परीक्षार्थियों का सत्यापन, निरूपण रोके जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक-19.०6.2०24 को जारी किए गये हैं। यह परीक्षा इन सभी मानकों के अनुसार की जा रही है।

लोकसभा में गूँजा अर्धसैनिक बलों के लिए पुरानी पेंशन का मुद्दा

नई दिल्ली। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में पुरानी पेंशन लागू हो, उन्हें भारत संघ के सशस्त्र बल माना जाए, अब यह मुद्दा संसद के मानसून सत्र में गूँजे लगा है। बुधवार को समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद धमेंद्र यादव ने सदन में कहा, अर्धसैनिक बलों के जवान बॉर्डर पर शहादत झेल रहे हैं, उन्हें पुरानी पेंशन दीजिए। गुरुवार को रोहतक के लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए पुरानी पेंशन की मांग उठाई। उन्होंने कहा, ये बल देश की सुरक्षा करते हैं, यहां तक कि संसद भवन की रक्षा का दायित्व भी यही बल निभाते हैं। इन्हें 1०० दिन का अवकाश



● **सपा सांसद धमेंद्र यादव ने उठाई आवाज** मिले। हर राज्य में सैनिक कल्याण बोर्ड की तर्ज पर राज्य अर्धसैनिक बोर्ड का गठन हो। सपा के सांसद धमेंद्र यादव ने कहा, जब भाजपा विपक्ष में रही तो ओपीएस की बात करती रही। यह सरकार अब 11 वां बजट पेश

कर रही है। देश के सरकारी कर्मचारी, पुरानी पेंशन के लिए परेशान हैं। सरकार, ओपीएस की चर्चा ही नहीं कर रही। लोकसभा में धमेंद्र यादव ने कहा, आप बहुत बड़े राष्ट्र भक्त बनते हैं। सीमा पर जवान शहादत झेल रहे हैं। केंद्रीय

अर्धसैनिक बलों के जवानों को पुरानी पेंशन दी जाए। उन्होंने कहा कि श्रद्धेय नेताजी ने हम समाजवादियों को न्याय और ईसाफ के लिए लड़ना सिखाया है जिस लड़ाई को हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। आज देश की 14० करोड़ आबादी में लगभग 95 फीसदी लोग बर्बाद हो चुके हैं, एनडीए सरकार के 11वें बजट में सबसे ज्यादा गरीबों को नजरअंदाज किया गया है, 2०14 में यूपीए सरकार में किसानों के लिये 5.5 फीसदी बजट था जो घटकर अब 3.15 फीसदी रह गया है, 2०13 में शिक्षा के लिये 4.77 था जो अब ढाई फीसदी रह गया

है। यह बजट पूरी तरह से गरीब विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, छात्र विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी तथा मजदूर विरोधी है। आगे कहा कि श्रद्धेय नेताजी ने कहा कि चुनाव में किये गए वादों को पूरा न करना भी एक भ्रष्टाचार होता है। कहीं है युवाओं को 2 करोड़ राजगार, कहीं है किसानों का डेड गुना समर्थन मूल्य। किसानों के खाद के कट्टे को दो बार में 1० किलो घटा दिया, इसी तरह चलता रहा तो आने वाले समय में कट्टे में सिर्फ 1० किलो ही यूरिया रह जायेगी। दिल्ली की सीमा पर सैकड़ों किसान शहीद हो गए पर इस संवेदनहीन सरकार को कोई



अमर भास्कर

आवश्यकता है-

अमर भास्कर

(हिन्दी दैनिक समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल)

को पूरे देश में प्रदेश स्तर, मण्डल स्तर, जिला स्तर, तहसील स्तर, ब्लॉक एवं थाना स्तर पर अनुभवी एवं शिक्षित संवाददाता एवं विज्ञापन प्रभारियों की।

संपर्क करें:-

मोबा. 9411214614, 9058143211, 7599339198

ऑफिस:-
जिकेट होटल रिजेन्सी, लावला चौक, बदायूं (उ.प्र.)- 243601

www.amarbhashkar.com
Email- amarbhashkar21@gmail.com

संपादकीय

विवेकशील, साहसी और समझदारी भरा बजट



नरेंद्र मोदी सरकार के अपने छठे पूर्ण बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को दिखाया कि वह राजकोषीय विवेक, साहस और राजनीतिक समझदारी सब रखती हैं। उनका राजकोषीय विवेक न केवल 2024-25 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कम करके सकल घरेलू उत्पाद के 4.9 फीसदी तक लाने में नजर आता है बल्कि उनकी इस घोषणा में भी दिखता है कि वह राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को 2026-27 से केंद्र सरकार के घाटे में कमी के साथ तालमेल वाला बनाएंगी।

वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटे के लिए 5.1 फीसदी का लक्ष्य तय किया गया था जिसका मतलब था कि सरकारी ऋण जीडीपी का 57.2 फीसदी होगा। मंगलवार को पेश बजट में घाटे के लिए 4.9 फीसदी का लक्ष्य तय किया गया जो सरकारी ऋण को कम करके जीडीपी के 56.8 फीसदी के स्तर पर लाएगा।

यकीनन कर्ज का यह स्तर अभी भी आधिकारिक समिति द्वारा कुछ माह पहले तय किए गए 40 फीसदी के लक्ष्य से अधिक है। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि मंगलवार तक कोविड के बाद के अपने सभी बजट भाषणों में यह लक्ष्य रखा गया कि राजकोषीय घाटे को 2025-26 तक जीडीपी के 4.5 फीसदी तक लाना है लेकिन सरकारी ऋण के स्तर में कमी का जिक्र करने की आवश्यकता नहीं समझी गई।

वर्ष 2024-25 के बजट भाषण में सीतारमण ने राजकोषीय घाटे को इस गति से कम करने का जिक्र किया जिससे कि सरकारी ऋण के स्तर में भी कमी आए। उन्होंने कहा, 2026-27 के बाद से हमारा प्रयास होगा कि राजकोषीय घाटे को ऐसा रखा जाए ताकि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भी केंद्र सरकार का ऋण गिरावट पर हो। यह एक स्वागतयोग्य और जरूरी बात है जिस पर सरकार को राजकोषीय मजबूती की रणनीति के तहत ध्यान देना आवश्यक था। एक विकासशील अर्थव्यवस्था की अलग तरह की दिक्कों को देखते हुए कर्ज के स्तर को राजकोषीय मजबूती के अधिक विश्वसनीय आधार के रूप में देखा जा रहा है।

सीतारमण के वित्तीय विवेक को एक और तरह से आंका जा सकता है। उन्होंने रिजर्व बैंक से अतिरिक्त लाभांश मिलने के बावजूद खुद को विभिन्न योजनाओं के लिए अतिरिक्त आवंटन करने से रोके रखा। यह लाभांश जीडीपी के 0.4 फीसदी के बराबर है। उन्होंने इस बात को सही चिह्नित किया कि यह इस वर्ष हुआ एकबारगी लाभ हो सकता है और अगले वर्ष शायद अतिरिक्त लाभांश मौजूद नहीं हो। ऐसे में इस वर्ष अतिरिक्त धनराशि होने के बावजूद उन्होंने राजस्व आवंटन को केवल छह फीसदी बढ़ने दिया। बिना ब्याज भुगतान के वास्तविक इजाफा 4.78 फीसदी रहा यानी लगभग कोई वृद्धि नहीं हुई। इसके बजाय उन्होंने पूंजीगत व्यय में 17 फीसदी इजाफा बरकरार रखा है। ऐसे में केंद्र सरकार का कुल व्यय 8.5 फीसदी बढ़ने वाला है जबकि उसका कुल राजस्व 15 फीसदी बढ़ेगा। आखिर में सीतारमण ने अपने व्यय की गुणवत्ता और मिश्रण में भी सुधार किया। इतना ही नहीं उन्होंने राजस्व घाटे को भी निरंतर कम किया। 2022-23 के जीडीपी के 4 फीसदी के मुकाबले राजस्व घाटा 2023-24 में 2.6 फीसदी रह गया और अब उसके लिए 1.8 फीसदी का लक्ष्य है। राजस्व घाटे में कमी के साथ ही सरकार के पास यह गुंजाइश होगी कि वह पूंजीगत व्यय में उधारी का अधिक हिस्सा खले। वित्त मंत्री इसलिए भी साहसी हैं क्योंकि उन्होंने हर प्रकार की परिसंपत्तियों से हासिल पूंजीगत लाभ पर कर का पुनर्गठन किया है। इसका परिणाम अल्पावधि और दीर्घावधि के पूंजीगत लाभ पर कर में इजाफे के रूप में सामने आया है। इसके अलावा उन्होंने प्रतिभूतियों के वायदा एवं विकल्प कारोबार पर लगने वाले प्रतिभूति विनियम कर (एसटीटी) में भी इजाफा किया है। याद रहे कि बजट के पहले आर्थिक समीक्षा में अर्थव्यवस्था के ज़रूरत से अधिक वित्तीयकरण के जोखिम को रेखांकित किया गया था। शेयर बाजार में वास्तविक अर्थव्यवस्था की तुलना में तेज वृद्धि इसमें शामिल है। समीक्षा में कर नीतियों और पूंजी और श्रम आय के साथ उसके व्यवहार के महत्व को भी रेखांकित किया गया है। ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री ने पूंजीगत लाभ कर और एसटीटी को लेकर जो घोषणाएं की हैं वे दरअसल समीक्षा में जताई चिंताओं की बदीलत हैं। परंतु जब बात सालाना बजट तैयार करने की आती है तो शेयर मार्केट के मामले में वित्त मंत्रियों को जोखिम से बचने के लिए जाना जाता है। कुछ ही वित्त मंत्री शेयर बाजार को निराश करने वाली घोषणा करते हैं। सीतारमण ने यह जोखिम उठाने का निर्णय लिया।

सदन की झलकियां, रंगों ने बताया सदन का माहौल

वर्ष 2019 के चुनावी साल में अंतरिम और पूर्ण बजट में जहां बहुत ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला था, इसके उलट इस बार के बजट और इसे लेकर आ रही प्रतिक्रियाओं में नई लोक सभा की झलक साफ दिखती है, जिसमें भाजपा सदस्यों की संख्या कम हो गई है और तेदेपा और जदयू पर सरकारी निर्भरता बढ़ गई है। बजट भाषण में बिहार और आंध्र प्रदेश का कई बार जिक्र किया गया।

जब बाढ़ से ग्रस्त बिहार जैसे राज्यों के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री ने मदद का ऐलान तो पुर्णकुलम से कांग्रेस सांसद हिबी इंडन ने सवाल उठाया कि केरल के लिए क्या दिया। इस पर तमाम सांसद हंसने लगे। इसके बाद वित्त मंत्री ने जब बिहार के नालंदा और राजगीर जैसे पर्यटन केंद्रों की विकास परियोजनाओं के लिए आवंटन का ऐलान किया तो द्रमुक सांसद दयानिधि मारन ने पूछा कि तमिलनाडु का क्या होगा? इसी प्रकार एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने कहा, यह आंध्र प्रदेश और बिहार का बजट है।

बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा कि अंतरिम और पूर्ण



बजट में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। उन्होंने कहा, 'मैं अंतरिम बजट के मूल भाव से बिल्कुल नहीं भटकी। आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज के बारे में उन्होंने कहा कि राज्य की नई राजधानी अमरावती को वित्तीय मदद देना बहुत जरूरी था। संभवतः लोक

सभा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब सदन में प्रवेश करते हुए लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला का स्वागत भारत माता की जय और अस्सलामुअलैकुम की गूंज के साथ हुआ। मोदी-मोदी और जय श्रीराम का नारे की आवाज इस बार बहुत

हल्की थी।

सदन में शुरुआत से ही बिहार के एक सांसद बार-बार कह रहे थे, 'कुर्सी बचाओ3'। सदन में शुरुआत से ही बिहार के एक सांसद बार-बार कह रहे थे, 'मैंडम, बिहार को भी कुछ दीजिए।' बजट भाषण में जब-जब आंध्र प्रदेश के शहरों-कस्बों का जिक्र आता तो कांग्रेस सांसद जोर-जोर से चिल्लाते,

'कुर्सी बचाओ3'

बजट भाषण के दौरान ऐसे भी क्षण आए जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से तालियों की गूंज सुनाई दी। कैंग्रेस का पता लगाने वाले कुछ उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी में छूट का जैसे ही ऐलान हुआ, दोनों

तरफ की मेजों पर तालियां बजने लगीं।

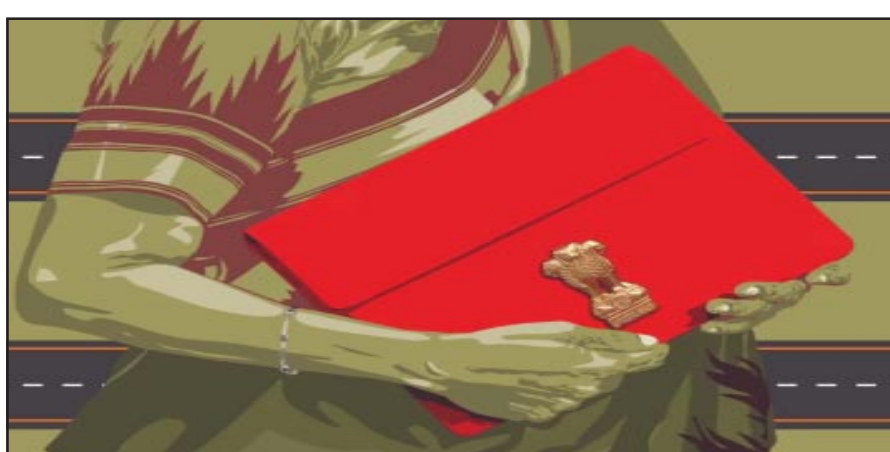
यही नहीं, अलग-अलग रंग सदन में बदले राजनीतिक परिदृश्य को भी परिलक्षित कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने लाल टोपी पहनी थी। वहीं, तुणमूल कांग्रेस के कुछ सांसद आसमानी रंग की जैकेट पहने हुए थे। इसके अलावा, भाजपा का भागवा और तेदेपा का रंग गहरा पीला भी खूब झलक रहा था। शायद पहली बार सदन की दर्शक दीर्घा में बड़ी संख्या में अतिथि भगवा पहने दिखाई दिए।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब घर से संसद जाने के लिए निकलीं तो उन्होंने अपनी बेटी वाग्मयी और अपने परिवार के अन्य सदस्यों को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। आज के लिए उन्होंने अपने पहनावे में हल्के मगर शानदार-शाही रंगों का चयन किया था। सीतारमण ने बैंगनी रंग के चैंडू बॉर्डर वाली जरी से सजी सफेद साड़ी पहनी थीं। मैसूर क्रेप सिल्क ऐसा कपड़ा है, जो कर्नाटक के अलावा कोई अन्य राज्य नहीं बुन सकता। इसमें उन्होंने अपने रंग के रंग का खास ख्याल रखा गया, जहां से चुनकर आती हैं।

पूंजीगत लाभ कर ढांचे को सहज बनाना बजट की अच्छी बात

मंगलवार को प्रस्तुत केंद्रीय बजट में एक अच्छी बात रही पूंजीगत लाभ ढांचे को सहज बनाना। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि चुनिंदा वित्तीय परिसंपत्तियों पर अल्पावधि का पूंजीगत लाभ कर 20 फीसदी की दर से लगाया जाएगा जबकि पहले यह 15 फीसदी की दर से लगाया जाता था। अन्य सभी वित्तीय एवं गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर उसी दर से कर लगेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि शेयर बाजार में अल्पावधि में होने वाले लाभ पर 20 फीसदी की दर से कर चुकता करना होगा। इसके अलावा सभी वित्तीय और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर होने वाले दीर्घकालिक लाभ पर 12.5 फीसदी की दर से कर लगेगा।

सूचीबद्ध शेयरों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर की दर 10 फीसदी थी। लंबी अवधि के कर और अल्पावधि के कर के बीच के अंतर



को बढ़ाने वाले कारणों में से एक पूंजी बाजार में दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा देना भी हो सकता है। खासतौर पर परिवारों द्वारा किए जाने वाले निवेश के मामले में।

निवेशकों की कम आय वाली श्रेणी की बात करें तो वित्त मंत्री ने पूंजीगत लाभ के मामले में रियायत की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर

1.25 लाख रुपये कर दिया है। सूचीबद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों को अगर एक वर्ष से अधिक अवधि तक रखा गया तो उन्हें दीर्घकालिक माना जाएगा।

गैर सूचीबद्ध वित्तीय और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में उन्हें दो वर्ष तक धारण करने पर ही उन्हें दीर्घकालिक माना जाएगा। गैर

सूचीबद्ध बॉन्ड और डिबेंचर और डेट म्यूचुअल फंड पर लागू दर से ही पूंजीगत लाभ कर लगेगा।

बजट के दिन सूचीबद्ध शेयरों पर पूंजीगत लाभ कर बढ़ाने की घोषणा ने शेयर बाजारों को प्रभावित किया। इसके चलते कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। हालांकि मानक सूचकांक ने कारोबार समाप्त

होते-होते काफी हद तक नुकसान की भरपाई कर ली।

अचल संपत्ति के क्षेत्र में भी चिंता थी क्योंकि पूंजीगत लाभ पर अब 12.5 फीसदी की दर से कर लगाया जाएगा और वह भी बिना इंडेक्सेशन लाभ के। पहले इंडेक्सेशन के साथ इस पर 20 फीसदी की दर से कर लगाया था। बहरहाल, जैसा कि सरकार ने स्पष्ट किया है, इससे अचल संपत्ति के अधिकांश निवेशकों को लाभ होगा। अगर लाभ का इस्तेमाल 10 करोड़ रुपये तक की कीमत का घर खरीदने या बनाने में किया जाएगा तो कर छूट मिलेगी। अगर चुनिंदा निवेश किया जाए तो भी छूट मिलेगी। प्रस्तावित बदलाव के दो परस्पर निर्भर लक्ष्य हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि मूल विचार है कर ढांचे को सरल बनाना। यह भी उम्मीद है कि सरल कर ढांचा कर संग्रह में सुधार

में मददगार साबित होगा। बाजार को बिना कठिनाई के उच्च कर दर से समायोजित हो जाना चाहिए। व्यापक स्तर पर देखें तो अगर अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन बेहतर बना रहता है, जो कि आय और शेयर कीमतों में तेजी के रूप में देखा जा सकता है तो बाजार को दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

कुछ विकसित देशों में पूंजीगत लाभ पर अधिक कर लगाता है। वित्तीय बाजारों से होने वाली आय पर उच्च कर भी प्रगतिशील कदम है। यह समाज का वह तबका है जो पूंजी बाजारों में निवेश करता है और उससे लाभान्वित होता है। बहरहाल, कराधान के मोर्चे पर अनिश्चितता निवेशकों को परेशान कर सकती है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह भी कहा कि सरकार अगले छह महीनों में आयकर अधिनियम 1961 की समीक्षा करेगी। समीक्षा के बाद पूंजीगत लाभ कर ढांचे में और बदलाव आ सकता है।

खेल-खिलाड़ी

पूर्व बल्लेबाजी कोच ने किया बड़ा खुलासा

नई दिल्ली। वनडे विश्व कप 2023 में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया था। रोहित शर्मा के नेतृत्व में टीम ने ग्रुप स्टेज पर लगातार 10 मैचों में जीत दर्ज की थी। हालांकि, फाइनल मैच में उन्हें ऑस्ट्रेलिया के हाथों करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इस मैच के बाद भारतीय टीम पर पिच के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगे थे।

इस पर अब पूर्व बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर ने सफाई पेश की है। उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया है। भारत की मेजबानी में वनडे विश्व कप 2023 का फाइनल



मुकामला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। पहले

बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम 50 ओवर में 240 रन पर ढेर हो गई थी।

जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने ट्रेविस हेड की 120 गेंदों पर 137 रनों की

घमाकेदार पारी की मदद से 43 ओवर में लक्ष्य का आसानी से पीछ कर लिया था। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने छह विकेट से जीत दर्ज कर खिताब पर कब्जा जमाया था। भारत की हार के बाद फाइनल के लिए इस्तेमाल की गई पिच की विश्व स्तर पर आलोचना हुई थी। अब पूर्व बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर ने इन आरोपों पर खुलकर बात की और कहा कि टीम प्रबंधन ने सोचा था कि जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ेगा, सतह धीमी होती जाएगी, लेकिन अंत में यह बल्लेबाजी के लिए बेहतर हो गई।

राठौर ने कहा, मैंने यह कहानी सुनी है कि पिच अलग थी, जिससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। फाइनल में, खेल आगे बढ़ने के साथ पिच को सुधार हुआ, हमें उम्मीद थी कि यह धीमी होगी, जो नहीं हुई, तो ऐसा क्यों हुआ हां, हम और रन बना सकते थे। बहुत सारे अगर-मार हैं, लेकिन एक बात पक्की है कि टूर्नामेंट जीतने के लिए आपको थोड़ी किस्मत की जरूरत होती है और उस दिन, ऑस्ट्रेलिया हमसे ज्यादा भाग्यशाली था। उन्होंने हमसे बेहतर क्रिकेट खेला। और यही कारण है कि वे जीते।

अमर भास्कर

(हिन्दी दैनिक समाचार पत्र)

- वरिष्ठ संरक्षक : वेदभानु आर्य
- संरक्षक : हमिद अली खॉं
- संरक्षक : सुरेश प्रसाद शर्मा
- प्रधान संपादक : फरीद क़ादरी
- संपादक : अबरार अहमद
- कानूनी सला. : मुहम्मद फ़ुरकान, एड.
- व्यवस्थापक : ठा. वेदपाल सिंह
- मैनेजर : केपी यादव

हमारे यूट्यूब चैनल **Amar Bhaskar News** को सब्सक्राइब करें वेल आइकॉन दबाना न भूलें।

-सर्वेश उपाध्याय, मैनेजिंग एडिटर*

अगर आपके पास भी है कोई कविता, रचना, लेख, गजल एवं छंद तो हमें लिख भेजिए, हमारा पता है:-

अमर भास्कर कार्यालय

निकट होटल रिजेन्सी, लावेलो चौक बदायूं (उ.प्र.)।

पिन कोड-243601

Email- amarbhaskar21@gmail.com
Whatsapp. No. 9411214614

पांच साल में होगी मेगा नीलामी, टीमों ने रिटेंशन को लेकर भी की यह मांग

नई दिल्ली। आईपीएल के 18वें सीजन से पहले इस साल मेगा नीलामी का आयोजन होगा। इस दौरान फ्रैंचाइजी खिलाड़ियों को रिटेंशन और रिलीज करना होगा। इससे पहले फ्रैंचाइजियों ने तीन बदलावों की मांग की है। इसमें मेगा नीलामी की अवधि, खिलाड़ियों के रिटेंशन की संख्या और राइट टू मैच के मुद्दे शामिल हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फ्रैंचाइजियों ने हाल ही में आईपीएल के अधिकारियों से मुलाकात की



धी। इस दौरान टीमों ने आईपीएल की। मेगा नीलामी से पहले हुई इस बैठक में फ्रैंचाइजियों ने मेगा

ऑक्शन की अवधि को पांच साल बढ़ाने की मांग की। इसके अलावा

टीमों को चार से छह खिलाड़ियों को रिटेंशन करने की इजाजत दी जाए और हर टीम को कम से कम दो राइट टू मैच (आरटीएम) का ऑप्शन दिया जाए। हालांकि, अब तक इनको लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है।

मेगा नीलामी को हर पांच साल में कराने की मांग के पीछे का कारण यह है कि इससे युवा खिलाड़ियों को तैयार होने का मौका मिलेगा। इससे अनकैप्ड खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा और वह अपने खेल

को सुधारने में कामयाब होंगे। बता दें, फिलहाल आईपीएल की मेगा नीलामी हर तीन साल में होती है।

इस मीटिंग में फ्रैंचाइजियों ने आईपीएल अधिकारियों से राइट टू मैच (आरटीएम) ऑप्शन में बदलाव की मांग की। टीमों चाहती हैं कि मेगा नीलामी से पहले इसे आठ कर दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो टीमों को अपने पुराने खिलाड़ियों को सबसे बड़ी बोली से मैच काइबर टीम में दोबारा शामिल करने में सहजता होगी।

गंगोत्री हाईवे पर आया फिर भारी मलबा-बोल्डर

अमर भास्कर, ब्यूरो
उत्तराखंड। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भटवाड़ी व गंगनानी के बीच में मलबा व बोल्डर आने के कारण बाधित हो गया। गंगोत्री हाईवे पर समस्या बरकरार है। बुधवार को भी बिशनपुर में बोल्डर और मलबा आने के कारण सुबह गंगोत्री हाईवे बंद हो गया। इसके चलते पैदल कांड यात्रियों के साथ ही कई वाहन हाईवे पर ही फंस गए थे।



बीआरओ ने हाईवे खोला जिसके बाद वाहनों की आवाजाही भी सुचारु हो गई। दरअसल, मंगलवार रात को

बोल्डर आने के कारण गंगोत्री हाईवे बंद हो गया। हालांकि बीआरओ ने नेताला और सैंज में करीब तीन घंटे की मशकत के बाद हाईवे पर वाहनों की आवाजाही शुरू करवा दी थी, लेकिन बिशनपुर में भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर आने के कारण हाईवे खोलने में मशकत करनी पड़ी। दोपहर तक जब हाईवे नहीं खुल पाया तो प्रशासन के निर्देश पर एनडीआरएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला। आज गंगोत्री हाईवे मलबा बोल्डर आने से भटवाड़ी व गंगनानी में बंद है। जिस कारण लोगों को लागातार समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

परिवार वाले शव दफनाने जा रहे थे, तभी सामने आ गया बेटा सरफराज

मुरादाबाद। छजलैट के खुशहालपुर गांव में चैंकाने वाला मामला सामने आया। एक दिन पहले लापता हुए सरफराज उर्फ नन्हे के परिजन और ग्रामीण करूला नदी में मिले शव को उसका समझकर दफनाने जा रहे थे। इसी दौरान सरफराज घर लौट आया। उसे देखकर परिजन खुशियां मनाते लगे।



मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया। साथ ही सरफराज व उसके परिजनों से पूछताछ की। छजलैट थाना क्षेत्र के खुशहालपुर निवासी सरफराज उर्फ नन्हे (35) का

गए। इसी दौरान गांव से करीब 700 मीटर दूर अमरोहा जनपद के सिहाली नारायणपुर गांव के पास करूला नदी में पुल के पास एक युवक का शव पड़ा दिखाई दिया। जानकारी मिलने पर सरफराज के परिजन भी पहुंच गए। उन्होंने अंगोछे और कपड़ों से शव की पहचान सरफराज के रूप में कर ली और शव को उठाकर घर ले आए। परिजन शव दफनाने जा रहे थे तभी सरफराज घर पहुंच गया। उसे सही सलामत देखकर परिजन व ग्रामीण हैरान रह गए। मामले की जानकारी मिलने पर छजलैट

सार-संक्षेप

कोटद्वार में गढ़वाल वीरता सम्मान 2024 का आयोजन, पहुंचे अतिथि



अमर भास्कर, ब्यूरो
देहरादून। कोटद्वार में आयोजित कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी एवं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचीं। कारगिल विजय दिवस पर अमर उजाला की ओर से गढ़वाल वीरता सम्मान 2024 का आयोजन किया गया। जिसका शुभारंभ सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी एवं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।

सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी ओम प्रकाश परसवान ने कारगिल विजय दिवस के संबंध में शौर्य गाथा सुनाई। डा. पद्मेश बुड़कोटी के संचालन में आयोजित कार्यक्रम में स्वाभिमान न्यास झंडीचढ़ योग टीम के युवाओं ने हैरतंगेज योगासन से भाव विभोर किया। राजकीय कन्या इंटर कॉलेज कोटद्वार की छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। आदर्श विद्या निकेतन हल्द्वारा की टीम ने मनमोहक बैड धुन के माध्यम से देशभक्ति भाव से ओतप्रोत प्रस्तुति दी। जीआईसी कोटद्वार के विद्यार्थियों ने जय याद करो कुर्बानी, गीत गाकर वीर जवानों को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों के परिजनों के अलावा एसडीएम सोहन सैनी, भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र रावत, शिवकुमार गुप्ता सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

डेटलाइन खत्म होने के बाद भी मसूरी अकादमी नहीं पहुंचीं ट्रेनी आईएएस अधिकारी



अमर भास्कर, ब्यूरो
उत्तराखंड। यूपीएससी में नियुक्ति को लेकर विवादों में आई ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर बुधवार को भी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी नहीं पहुंच सकी। उनको 23 जुलाई तक अकादमी पहुंचकर रिपोर्ट करनी थी। तब डेटलाइन खत्म होने के बाद भी वह अकादमी नहीं पहुंचीं।

ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर गलत मेडिकल रिपोर्ट और तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने और आरक्षण आदि कई आरोपों से घिरी हैं। आरोपों की जांच चल रही है। पूजा खेडकर को 23 जुलाई तक अकादमी में पहुंचना था, लेकिन वह 24 जुलाई तक भी नहीं पहुंचीं हैं। सूत्रों के मुताबिक अकादमी नहीं पहुंचने पर अकादमी प्रशासन की ओर से ट्रेनी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने पर विचार किया जा रहा है।

12 गांवों के प्रधान और सचिवों के खिलाफ गबन की जांच शुरू



अमर भास्कर, ब्यूरो
मुरादाबाद। ग्राम पंचायत के खालों से सरकारी धन निकालने और उसका हिसाब नहीं मिलने पर 12 से अधिक गांवों के प्रधान और सचिव की जांच शुरू हो गई है। सीडीओ के नेतृत्व में एक टीम 18 बिंदुओं पर जांच कर रही है। जांच रिपोर्ट विधानसभा की उच्च समिति को सौंपी जाएगी।

सीडीओ वाचस्पति ने बताया कि विधानसभा की उच्च समिति के समक्ष पेश हुए थे। समिति के समक्ष उन्होंने 2016-17 के पंचायत के खालों से विकास कार्यों के एवज में हुए सरकारी धन के लेनदेन मामले की ऑडिट रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। इस मामले में समिति ने सात बिंदुओं पर सहमति जताई लेकिन 18 अन्य बिंदुओं पर सीडीओ के नेतृत्व में समिति गठित कर जांच करने के निर्देश दिए। आरोप है कि 18 बिंदुओं पर ऑडिट टीम ने आपत्ति लगाई थी। इस मामले में सीडीओ ने जांच के लिए एक समिति गठित की है। इसमें

किशोरी का जबरन धर्म परिवर्तन, युवक से कराया निकाह



मझोला। थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय किशोरी को अगवा कर उसका धर्म परिवर्तन करा दिया गया। इसके बाद किशोरी का एक युवक से निकाह भी करा दिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवक और उसके भाइयों खिलाफ केस दर्ज किया है।

पुलिस किशोरी की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी है। किशोरी की मां ने मझोला थाने में केस दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी बेटी कक्षा नौ में पढ़ती है। 21 जुलाई को वह घर से गायब हो गई। काफी तलाश के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लगा। बाद में उसे पता चला कि राजा बाबू अपने भाई मेहरबान अली, शमशेर अली निवासी रेलवे हरथला कॉलोनी की मदद से उसकी बेटी को अगवा कर ले गया है। महिला ने आरोपियों के घर बेटी के बारे में पूछने गई तो आरोपी उसे धमकी देने लगे कि अगर केस दर्ज कराया तुम्हारे बेटे की हत्या कर देंगे। हमने किशोरी का धर्म परिवर्तन कराकर

राजा बाबू से उसका निकाह करा दिया है। अब उसकी तलाश बंद कर दो। सीओ सिविल लाईंस अर्पित कपूर ने बताया कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। मझोला थाने में दर्ज कराए जाने वाले एक अधिवक्ता ने चंडौसी निवासी अधिवक्ता पर भगवान श्रीराम पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में केस दर्ज कराया है। बुद्धि विहार निवासी अधिवक्ता विजेंद्र सिंह ने मझोला थाने में दर्ज कराए केस में बताया कि 19 अप्रैल 2024 को वह अपने साथी शरद वर्मा, सुरेश पाल, अरविंद मोहन के साथ रात में टहल रहे थे।

दिव्यांगों ने प्रधान मंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा

अमर भास्कर, ब्यूरो
संभल। उपजिलाधिकारी कार्यालय पर राष्ट्रीय विकलांग एवं महिला शक्तिकरण विकास फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद कासिम के नेतृत्व में दिव्यांग एकत्र हुए और अपनी मांगों को लेकर प्रधान मंत्री को संबोधित 11 सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम संभल को सौंपा गया।



संस्थाओं की मदद से जमीनी स्तर पर प्रचार प्रसार हो ताकि अधिक से अधिक दिव्यांग इन सुविधाओं का लाभ ले सकें। दिव्यांगों को शिक्षा से जोड़ने के लिए उचित प्रबंध कराये जायें। दिव्यांगता की वजह से अधिकतर

जानकर उचित समाधान किया जाय। बौद्धिक अक्षमता वाले दिव्यांग एवं 80 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगों का जीवित होने का वेरिफिकेशन घर बैठ कर शुरू किया जाये। बौद्धिक दिव्यांगों के लिए ब्लॉक स्तर पर डे केयर एवं पुनर्वास केंद्र खोले जायें जहां उनके माता पिता उनको छोड़कर आजीविका कमाने जा सकें और उन्हें उचित ध्यान मिल सके। देखने में आया है ऐसे लोगों को घर पर जंजीरों से बांध कर या कमरे में बंद छोड़कर जाया जाता है। दिव्यांगों का वर्ष 2016 का एकट सरकार द्वारा जमीनी स्तर पर लागू करना चाहिए।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आईजीआरएस पोर्टल से संबंधित समीक्षा बैठक का किया गया आयोजन

संभल। कलेक्ट्रेट सभागार बहजोई में जिलाधिकारी डॉ राजेंद्र पैसिया की अध्यक्षता में आईजीआरएस पोर्टल से संबंधित समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें डिप्टी कलेक्टर वंदना मिश्रा ने विभिन्न विभागों की आईजीआरएस पोर्टल पर लंबित शिकायत एवं डिफॉल्टर शिकायत एवं शिकायतों के निस्तारण के संबंध में जिलाधिकारी को अवगत कराया।

जिससे कोई शिकायत लंबित न रहे। जिला पूर्ति अधिकारी की लंबित शिकायतों को लेकर जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी से कहा कि तहसील गुजौर के ग्राम चबूतरा की शिकायत जो की लंबित है। उसका स्थलीय निरीक्षण करते हुए निस्तारण करें

कहा कि यथाशीघ्र शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आगामी बैठक में आईजीआरएस देख रहे कंप्यूटर ऑपरेटरों को भी बैठक में साथ लेकर आए। जिससे लंबित शिकायत के बारे में अच्छे से समझ सकें।

को निर्देशित करते हुए कहा कि कार्यालयों में साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाय। कार्यालयों में कोई भी धूम्रपान करते पाया जाए तो उस पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी गोरखनाथ भट्ट, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर तरन्तुम रजा, उप जिलाधिकारी चंडौसी नीतू रानी, उप जिलाधिकारी संभल विनय कुमार मिश्रा, परि योजना निदेशक डीआरडीए ज्ञान सिंह, डिप्टी कलेक्टर वंदना मिश्रा, उषेंद्र कुमार पांडेय एवं संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

कारगिल विजय दिवस पर भाजपा युवा मोर्चा ने निकाला मशाल जुलूस, लगाई प्रदर्शनी

धूम्रपान निषेध अधियान: उच्च प्राथमिक विद्यालय मात्र एक अनुदेशक के सहारे शिक्षा विभाग बैठा मौन

अमर भास्कर, ब्यूरो
संभल। जिले में जिलाधिकारी राजेंद्र पैसिया ने जनपद संभल का चार्ज संभालते ही जनपद संभल में शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों का विशेष ध्यान रखते हुए सबसे पहले शिक्षा विभाग को संज्ञान में लिया है। क्योंकि अधिकतर परिषदी, विद्यालयों में गरीब बच्चे ही शिक्षा पाने के लिए जाते और उनके अधिभावकों के पास इतना पैसा नहीं होता जिससे कि मॉडर्न स्कूलों में प्रवेश दिला सकें। लेकिन जिलाधिकारी के इतना बड़ा संज्ञान लेने के बाद भी शिक्षा विभाग आंखें बंद करके बैठा हुआ है।

कारगिल विजय दिवस पर भाजपा युवा मोर्चा ने निकाला मशाल जुलूस, लगाई प्रदर्शनी

कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष में मशाल जुलूस निकाला। जुलूस का आयोजन युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष कुलदीप प्रतिहार के नेतृत्व में हुआ। मशाल जुलूस बारह पथर मैदान से शुरू होकर मुख्य बाजार, घंटाघर, नरदई गेट स्थित रानी लक्ष्मी बाई कम्प्यूनिटी हॉल प्रभु पार्क संपन्न हुआ।

कारगिल विजय दिवस पर भाजपा युवा मोर्चा ने निकाला मशाल जुलूस, लगाई प्रदर्शनी

कारगिल विजय दिवस पर भाजपा युवा मोर्चा ने निकाला मशाल जुलूस, लगाई प्रदर्शनी



प्रचार के लिए कमला ने जुटाई करोड़ों की रकम

वाशिंगटन। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में लगातार हलचल मची हुई है। यहां आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। रिपब्लिकन की ओर से डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट्स की तरफसे कमला हैरिस मैदान में हैं। दोनों प्रतिद्वंद्वी एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इस बीच, ट्रंप की प्रचार टीम ने संघीय चुनाव आयोग में एक शिकायत दी है।

उनका कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की प्रचार टीम द्वारा जुटाए गए धन को उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को नहीं सौंपा जा सकता। ट्रंप की प्रचार टीम के वकील डेविड वरिंगटन ने मंगलवार को शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने तर्क दिया कि हैरिस की प्रचार टीम को धन सौंपना 1971 के संघीय चुनाव अभियान अधिनियम का खुलेआम उल्लंघन होगा। हालांकि, हैरिस की प्रचार टीम ने इन आरोपों को निराधार



बताया। वरिंगटन ने बाइडन द्वारा हैरिस को करीब 10 करोड़ डॉलर का योगदान देने का आरोप लगाया है। उन्होंने शिकायत में कहा कि यह इतिहास में सबसे बड़ा उल्लंघन है। आयोग चुप नहीं बैठ सकता, जब एक उम्मीदवार इतना धन ले रहा है। यह पूरी तरह से गलत है। उनका कहना है, एकमला हैरिस जो बाइडन के प्रचार अभियान द्वारा जुटाए गए 9.15

उनकी अधिकृत समिति के नाम पर दिखाई देना चाहिए। लेकिन कमला हैरिस का नाम उनकी कथित अधिकृत समिति, राष्ट्रपति पद के लिए बाइडनशू के नाम पर नहीं दिखाई देता है और रविवार तक उनके लिए उम्मीदवारी का कोई बयान मौजूद नहीं था।

हैरिस की प्रचार टीम के प्रवक्ता चार्ल्स क्रेचमर लुटवाक ने मंगलवार को शिकायत का जवाब देते हुए कहा, रिपब्लिकन जल सकते हैं कि डेमोक्रेट डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगियों को हराने के लिए उत्साहित हैं, लेकिन आधारहीन कानूनी दावे केवल उनका ध्यान भटकाने के लिए हैं, जबकि हम स्वयंसेवकों को शामिल कर रहे हैं, मतदाताओं से बात कर रहे हैं और यह चुनाव जीत रहे हैं। एफएचसी के एक प्रवक्ता ने प्रवर्तन मामलों पर चर्चा नहीं करने पर एजेंसी की नीति का हवाला देते हुए टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

कोर्ट डॉलर को पाने की कोशिश कर रही है। यह संघीय चुनाव अभियान अधिनियम 1971 के इतिहास में सबसे अधिक योगदान और उल्लंघन होगा।

उन्होंने आगे कहा कि अगर कमला हैरिस 2024 में किसी पद के लिए उम्मीदवार होंगी, तो संघीय कानून के अनुसार उन्हें उम्मीदवारी का एक बयान दखिल करना होता और उनका नाम

सबसे बड़ी अधीनस्थ कोर्ट में कामकाज ठप

वाशिंगटन। अमेरिका की सबसे बड़ी अधीनस्थ अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ लॉस एंजिलिस काउंटी पिछले सप्ताह रैनसमवेयर हमले के कारण बंद रही। अदालत के अधिकारियों ने बताया कि यह सप्ताह तक बंद रही। अदालतें शुक्रवार को काम-काज के लिए खुली रहीं लेकिन काउंटी की सभी 36 अदालतें सोमवार को नहीं खुलीं। पीटासीन जज सामंथा पी. जेसनर ने कहा, कोर्ट में अप्रत्याशित साइबर हमले से क्षति रोकने, सूचना की अखंडता-गोपनीयता को रक्षा करने तथा भविष्य में नेटवर्क स्थिरता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगभग सभी नेटवर्क प्रणालियों को बंद करना पड़ा। अब सभी 36 अदालतें भारतीय समयानुसार पुनरुद्धार को खुलेंगी। अधिकारियों ने कहा, यह हमला माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से उपकरणों के प्रभावित होने की घटना से जुड़ा हुआ नहीं है।



जुकुरशमल। हमारा और इसाइल बीते नौ महीने से जंग लड़ रहे हैं। इसाइल द्वारा हमारा को खत्म करने का संकल्प गाजा पट्टी के लोगों पर भारी पड़ रहा है। गाजा में पैदा हुई मानवीय परिस्थितियों को लेकर देशभर में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस बीच जानकारी सामने आई है कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस इस सप्ताह व्हाइट हाउस में इसाइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगी। हालांकि, वह संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता नहीं कर पाएंगी। आगे कहा, शहमें उम्मीद है कि उपराष्ट्रपति अपने विचार व्यक्त करेंगी कि अब समय आ गया है कि युद्ध को इस तरह समाप्त किया जाए कि इसाइल सुरक्षित हो, सभी बंधकों को रिहा किया जाए, गाजा में फ्लस्तीनी नागरिकों की पीड़ा समाप्त हो और फ्लस्तीनी लोग सम्मान, स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के अपने अधिकार का आनंद ले सकें। वे युद्धविराम समझौते पर सहमति बनाने के प्रयासों पर चर्चा करेंगी। नेतन्याहू बुधवार

भारत एक रणनीतिक साझेदार: राइडर

वाशिंगटन। अमेरिका का रक्षा विभाग आप दिन भारत के साथ अपने संबंधों को सराहाता दिखाता है। एक बार फिर पेंटागन ने साफकर दिया कि भारत एक रणनीतिक सहयोगी है और अमेरिका इस साझेदारी को विकसित करने के लिए तय है। पेंटागन के प्रेस सचिव पीट राइडर ने मंगलवार को वाशिंगटन में एक संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत एक रणनीतिक साझेदार है।

हम इस साझेदारी को आगे विकसित करते देखना चाहते हैं। एशिया-पैसिफिक में संघर्ष पर राइडर ने कहा, राजब बात यूक्रेन और रूस के अवैध कब्जे और यूक्रेन पर हमले की बात आती है। आखिरकार यह यूक्रेन पर निर्भर करता है कि वह कब शांति के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है। उन्होंने आगे कहा,



अभी हमारा ध्यान यूक्रेन के साथ काम करने पर है ताकि उन्हें अपने देश की रक्षा करने, अपनी संप्रभुता की रक्षा करने और अपने क्षेत्र को वापस लेने के लिए जरूरी मदद की जा सके। हालांकि, यूक्रेन के बिना यूक्रेन के बारे में कोई फैसला नहीं लिया जा सकता है। एक अधिकारी ने पिछले महीने बताया था कि तीसरा इंडस-एक्स शिखर सम्मेलन सितंबर 2024 में सिलिकॉन वैली में होगा, जिसमें रक्षा नवाचार के लिए निजी पूंजी का

दक्षिण अटलांटिक में मछली पकड़ने वाली नाव डूबी

नई दिल्ली। दक्षिण अटलांटिक महासागर में मछली पकड़ने वाली नाव डूबने से छह लोगों की मौत हो गई और सात लोग लापता हो गए हैं। ब्रिटिश और स्पेनिश समुद्री अधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा कि फ्रेंकलैंड द्वीप समूह के तट से लगभग 200 मील दूर नाव सवार 27 लोग मछली पकड़ने जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। स्पेनिश अधिकारियों ने बताया कि ऑगोस जॉर्जिया नामक 176 फुट की जहाज अर्जेंटीना के पास दक्षिण अटलांटिक महासागर में डूब गई। जिसके बाद किसी तरह नाव से चौदह लोगों को बचाकर जीवनरक्षक नौका पर चढ़ाया गया। इसके अलावा दो अन्य नावों को भी बचा लिया गया। दक्षिणपूर्वी गैलिसिया में स्पेन के पोर्टवेदा प्रांत के अधिकारियों ने बताया कि चालक दल के 10 सदस्यों की पहचान स्पेन के लोगों के रूप में की गई है।

चौरासी साल में सबसे गर्म रहा जुलाई का यह दिन

नई दिल्ली। जलवायु परिवर्तन के भयानक परिणाम दिखने शुरू हो गए हैं। दुनियाभर में भीषण गर्मी, बाढ़, बेमौसम बरसात जैसी घटनाएं आम हो चुकी हैं। इस बीच वैश्विक स्तर पर तापमान के परिवर्तन पर नजर रखने वाली एजेंसी ने जलसा देने वाली गर्मी को लेकर आंकड़े जारी किए। पिछले हफ्ते अमेरिका समेत यूरोपीय देशों में लू और गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया था।

ताजा आंकड़ों के अनुसार 21 जुलाई सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए दुनिया के इतिहास का अब तक का सबसे गर्म दिन बन गया है। इस दिन औसत तापमान पिछले 84 वर्षों के तुलना में अधिक दर्ज किया गया। लंदन स्थित यूरोपीय संघ की कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा के अनुसार, पहली बार वैश्विक औसत सतही वायु तापमान 17.09 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।



जिसने पिछले साल जुलाई के तापमान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले साल 17.08 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया थारिपोर्ट में कहा गया कि पिछले सप्ताह संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और रूस के बड़े हिस्से में भीषण गर्मी का प्रकोप देखा गया।

कोपरनिकस का कहना है कि 21 जुलाई को इस बार दैनिक औसत तापमान का पुराना रिकॉर्ड टूट गया। तूफ के उन इलाकों में भी लोगों के पसीने निकल रहे थे, जहां ठंड होती

कि पिछले 13 महीनों में तापमान और पिछले रिकॉर्ड के बीच का अंतर चौका देने वाला है। जैसे-जैसे जलवायु गर्म होती जा रही है, हम आने वाले महीनों और वर्षों में एर रिकॉर्ड देखेंगे। दुनिया बड़े पैमाने पर जलवायु परिवर्तन के संकट को टालने के लिए विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार करने के कगार पर खड़ी है।

जुलाई इस तथ सीमा के करीब पहुंचने का लगातार 13वां महीना है। सीउएस के वैज्ञानिक के मुताबिक, पिछले साल जून के बाद से ही महीना रिकॉर्ड पर सबसे गर्म महीना रहा है। कोपरनिकस के अनुसार जून 2023 से लेकर लगातार 13 महीने की बात करें तो पर्यावरण में तेजी से बदलाव देखने को मिले हैं। उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का प्रकोप अधिक देखने को मिला है। 21 जुलाई ग्रह पर सबसे गर्म दिन रहा है।

डेमोक्रेट कार्यकर्ताओं को ऊर्जा से भर दिया

वाशिंगटन। अमेरिका में पांच नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। ऐसे में, रिपब्लिकन की ओर से डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट्स की तरफसे कमला हैरिस मैदान में हैं। हालांकि, यह निश्चित नहीं है, लेकिन बहुत संभावना है कि भारतीय मूल की हैरिस डेमोक्रेटिक उम्मीदवार होंगी। इन सबसे बीच, पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की प्रचार टीम के गुप्त दस्तावेज सामने आए हैं।

दस्तावेजों में यह माना गया है कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के राष्ट्रपति अभियान ने डेमोक्रेट्स के कार्यकर्ताओं को ऊर्जा से भर दिया है। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ है, उसे देखते हुए इसमें कोई संदेह नहीं है कि डेमोक्रेट कन्वेंशन से पहले ही उन्हें राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी मिल जाएगी। पूर्व राष्ट्रपति की प्रचार



टीम के सर्वश्रेष्ठ टोनी फ्रैंजीजियो के गुप्त दस्तावेज में ट्रंप के कार्यकर्ताओं को आश्चर्य करने की कोशिश की गई है कि जैसे-जैसे चुनाव प्रचार अभियान जोर पकड़ेगा, चीजें रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में बदल जाएंगी। आगे कहा गया है, सार्वजनिक चुनाव थोड़े समय में बदल सकते हैं और हैरिस डेमोक्रेट का आधार थोड़ा और मजबूत कर

अधिक लोगों से 10 करोड़ डॉलर जुटाए हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि उनके पक्ष में भारी समर्थन है। वहीं, ट्रंप की टीम की चिंताएं बढ़ गई हैं। फ्रैंजीजियो ने कहा, श्रमजने वाले समय में हैरिस को लेकर मीडिया में काफी हद तक सकारात्मक खबरें होंगी।

इससे निश्चित रूप से कम समय में डेमोक्रेट्स को एक ऊर्जा मिलेगी। उन्होंने कहा, इसका मतलब है कि हम सार्वजनिक सर्वश्रेष्ठ देखेंगे, जिसमें हैरिस राष्ट्रपति ट्रंप पर बढ़त बना रही है या उनसे आगे निकल रही हैं। जाहिर है, आज हम जिस स्थिति में हैं, वह पूरी तरह से अलग है। ऐसा पहले नहीं देखा गया है। मगर कुछ चीजें हैं जो नहीं बदली हैं। उन्हें ट्रंप को दस्तावेज में बताया, हमारे बेहद सफल कन्वेंशन समेत पिछले दो सप्ताह से प्रचार चल रहा है।

न्यूनतम वेतन विधेयक बिल पारित किया

नाइजीरिया। देश में संघीय कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन को दोगुना करने के लिए विधेयक पारित हो गया है। राष्ट्रपति बोला अहमद टुनुबू द्वारा विधेयक पर अपनी सहमति देने के बाद मासिक न्यूनतम वेतन 30,000 से बढ़कर 70,000 नायरा कर दिया गया है। इसके साथ ही अधिकारियों ने जीवनाभ्यास पर बढ़ती लागत को लेकर भी चेतावनी दी है। अफ्रीका के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश नाइजीरिया में हाल के महीनों में श्रमिकों ने कई हड़तलों की हैं। अधिकतर यूनिबन लगातार वेतन वृद्धि का दबाव बना रहे थे। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेद्रो ने इस दक्षिण अमेरिकी देश में सांड़ों की लड़ाई पर प्रतिबंध वाले विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

ट्रंप का दौर अश्वेत अमेरिकियों के लिए नरक: बाइडन

वाशिंगटन। अमेरिका में जैसे-जैसे राष्ट्रपति चुनाव का समय करीब आ रहा है, दोनों प्रतिद्वंद्वी खेमां-डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के बीच जुबानी जंग बढ़ती जा रही है। नेवादा में एक सभा के दौरान डेमोक्रेट नेता और राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा, हमारी राजनीति हिंसा से जुड़ी है, इसका मतलब यह नहीं है कि हमें सच बोलना बंद कर देना चाहिए।

आप कौन हैं, आपने क्या किया है, आप क्या करेंगे, यह सब जायज सवाल हैं। बाइडन ने 33वें अमेरिकी राष्ट्रपति हेरी ट्रूमैन के एक कथन का जिक्र कर कहा, श्रुनैन ने कहा था कि मैंने कभी किसी को नरक नहीं दिया। मैंने सिर्फ सच बताया और उन्हें लगा कि यह नरक है। बकौल बाइडन, इस कथन में वो सच्चाई छिपी है



जिससे साफ पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति काल अश्वेत अमेरिकियों के लिए नरक क्यों था। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन ने कहा, इस देश में किसी भी अन्य कारण की तुलना में ज्यादा बच्चे गोली लगने से मरते हैं, जो चीकानो वाला है।

यह परेशान करने वाला है और अगर हम इसके बारे में कोई ठोस निर्णय नहीं लेते तो यह सरासर कायरता होगी। उन्होंने कहा, अगर

आप अमेरिका में हिंसा के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं, तो अमेरिका की सड़कों से युद्ध वाले इन हथियारों को हटाने में मेरा साथ दें। बकौल बाइडन अपने चार साल के कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने लाखों अश्वेत अमेरिकियों को उनके स्वास्थ्य बीमा से बाहर निकालने के लिए ओबामाकेयर को निरस्त करने की कोशिश की थी। उन्होंने दो ट्रिलियन डॉलर की कर कटौती की। इसका सबसे ज्यादा फायदा सुपर-धनी, सबसे बड़ी कॉर्पोरेशन को हुआ। संघीय ऋण में इतना उछाल आया जिससे निपटना किसी भी राष्ट्रपति के एक कार्यकाल में संभव नहीं। यह राशि किसी भी राष्ट्रपति के पूरे कार्यकाल में लिए गए ऋण से ज्यादा हो गया।

इस्त्राइली हमलों में मारे गए 60 से ज्यादा फलस्तीनी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के अशांत खेबर-पखूनखा प्रांत में एक सैन्य छावनी पर आतंकी हमले में आठ सैनिकों की मौत हो गई। सेना ने जवाबी कार्रवाई में 10 आतंकों के मारे जाने का दावा किया है। आतंकों ने बन्नु छावनी को निशाना बनाया। एक अन्य घटना में डेरा इस्माइल खान जिले में आतंकों ने स्वास्थ्य केंद्र पर हमला किया।

इसमें दो सुरक्षाकर्मियों सहित सात लोग मारे गए। मध्य गाजा पट्टी में मंगलवार को इस्राइली हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 24 लोग मारे गए। नुसीरात और जवैदा में 10 महिलाएं और चार बच्चे मारे गए



हैं। खान यूनिफ पर एक कार पर इस्राइली हवाई हमले में 17 की मौत हुई जबकि 26 घायल हो गए। गत वर्ष 7 अक्टूबर के बाद से हुए इस्राइली हमलों में अब तक 38,600 मौतें हो चुकी हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के उपस्थिति प्रतिनिधि आर वरिंद ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में खुली बहस में भारत का

पक्ष रखा। उन्होंने कहा, भले ही हम एक और विश्व युद्ध रोकने में सफल रहें, लेकिन ऐसा करना जटिल वैश्विक चुनौतियों का माकूल जवाब देने में संयुक्त राष्ट्र की अक्षमता की असलियत को नहीं छिपा सकता। राजदूत रवींद्र ने आतंकवाद, महाभारती, जलवायु परिवर्तन, उभरती प्रौद्योगिकियों से पैदा होने वाले खतरों, साइबर हमलों और राज्य विरोधी तत्वों की विघटनकारी भूमिका को बेहद जटिल चुनौती करार दिया। राजदूत रवींद्र ने कहा, हम संयुक्त राष्ट्र के मंच पर बहुध्रुवीयता के बारे में बात कर रहे हैं।

चुनाव स्वतंत्रता और अराजकता के बीच का है एक विकल्प

अमेरिका। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती देने के लिए अपनी डेमोक्रेट पार्टी के डेलीगेट का समर्थन जुटाने के लिए मंगलवार को अपनी पहली रैली के लिए विस्कॉन्सिन पहुंचीं। इस दौरान मतदाताओं की भारी भीड़ ने हैरिस का जोरदार स्वागत किया। हैरिस ने मतदाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 का राष्ट्रपति चुनाव स्वतंत्रता और अराजकता के बीच विकल्प होगा। हैरिस ने कहा, इस अभियान में, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपना रिकॉर्ड सप्ताह के किसी भी दिन उनके के खिलाफ रखूंगी।

राष्ट्रपति पद की दौड़ से हटने के बाद बाइडन राष्ट्र को संबोधित करेंगे

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन राष्ट्रपति पद की दौड़ से हटने के बाद बुधवार को राष्ट्र को संबोधित करेंगे। अपने संबोधन में बाइडन अपने देशवासियों को अपने फैसले के बारे में बताएंगे और नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी डिटी क्मला हैरिस का समर्थन करेंगे।

बिडेन ने मंगलवार को कहा, कल शाम 8 बजे मैं ओवल ऑफिस से राष्ट्र को संबोधित करूंगा कि आगे क्या होने वाला है, तथा मैं अमेरिकी लोगों के लिए काम कैसे पूरा करूंगा। यह इस महीने दूसरी बार होगा जब बिडेन राष्ट्र को संबोधित



करेंगे। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ट्रंप पर हत्या की असफल कोशिश के एक दिन बाद 14 जुलाई को देश को संबोधित किया था। कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद अमेरिका

के राष्ट्रपति जो बाइडन पहली बार बुधवार को सार्वजनिक तौर पर दिखाई दिए। जो बाइडन की अनुपस्थिति को लेकर सोशल मीडिया पर अपन्नाहों का दौर चल रहा था। दरअसल कोरोना संक्रमण के चलते

आइसोलेशन में रहने के दौरान ही बाइडन ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से हटने का एलान किया था। यही वजह है कि बाइडन की अनुपस्थिति को लेकर अपन्नाहों का दौर शुरू हो गया था। सोशल मीडिया पर चल रही अपन्नाहों में कहा जा रहा था कि 81 वर्षीय जो बाइडन की सेहत लगातार खराब हो रही है। कुछ लोगों ने यहां तक दावा कर दिया कि बाइडन की हालत इतनी गंभीर है कि उनका बचना अब मुश्किल है। सोशल मीडिया पर जो कहा है ट्रेंड भी करने लगा था। हालांकि अब सार्वजनिक तौर पर बाइडन के दिखाई देने पर इन सभी अपन्नाहों पर रोक लग गई है।